



High Court Bar Association, Allahabad

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद

President

Rakesh Pande 9415305760

Hony. Secretary

J. B. Singh 9450376768

Senior Vice President

Akhilesh Kumar Mishra 9450590540
"Gandhi"

Vice President

Virendra Nath Upadhyay 9450626097
Shri Kant Kesarwani 9450048085
Ajeet Kumar Yadav 9450431224
Saurabh Tiwari 9532435231
Vijay Singh Sengar 9935617500

Joint Secretary (Administration)

Priyadarshi Tripathi 9415812813

Joint Secretary (Library)

Ashutosh Pandey 9415241621

Joint Secretary (Press)

Sarvesh Kumar Dubey 9335306090

Joint Secretary (Women)

Smt. Nilam Shukla 9415123870

Treasurer

Surendra Nath Mishra 9450635316

Members of Governing Council

Anchal Ojha 8726456015
Shivangi Bhargava 9889062337
Ajay Kumar Mishra 9695322382
Manish Pandey 9307470123
Ashutosh Kumar Mishra 9651003743
Barun Kumar Shukla 8004828005
Ambuj Kumar Shukla 9936152855
Santosh Kumar Mishra 9919387580
Indu Shekhar Tripathi 9415368312
Vinod Kumar Yadav 9415650129
Abhishek Kumar Saroj 9838321075
Ashok Kumar Mishra 9455407577
Urmila Tripathi 9451853052
Kapil Dev Yadav 9935300143
Ajay Kumar Pathak 7271832630

Ref. : No. H.C.B.A./.....

Dated :18.08.2019.

गौरव बढ़ाने का प्रयास कर रहा है दूसरी ओर न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार पर अंकुश लगाकर, जो अपनी निर्भीकता, स्वतन्त्रता व निष्पक्षता के लिए विश्व में जाना जाता है, पर आघात कर रहा है। आज भी उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में न्यायपालिका के ऊपर नागरिकों का पूरा विश्वास है। किसी भी देश में प्रजातन्त्र की रक्षा के लिए न्यायपालिका का सशक्त होना आवश्यक है। प्रयागराज शिक्षा, न्यायपालिका तथा संगम के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। शिक्षा के क्षेत्र में बेसिक शिक्षा परिषद, शिक्षा निदेशालय, पुलिस मुख्यालय आदि सरकारी कार्यालयों को प्रयागराज से लखनऊ स्थानान्तरित कर उसकी गरिमा पर आघात किया गया है। प्रयागराज से विभिन्न न्यायिक अधिकरणों को लखनऊ स्थानान्तरित कर उसकी स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता पर आघात किया गया है। शैक्षिक सेवा अधिकरण की लखनऊ में स्थापना किया जाना बहुत ही सशक्त इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिकारों पर आघात है।

श्रद्धेयवर, विगत कई दिनों से मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अधिवक्ता "शैक्षिक सेवा अधिकरण" को लखनऊ में स्थापित किए जाने के निर्णय के विरोध में आन्दोलनरत हैं। उक्त अधिकरण की लखनऊ में स्थापना अधिवक्ताओं के साथ-साथ नगर के व्यवसायों एवं अन्य नगरवासियों की आर्थिक स्थिति प्रभावित करेगा। उक्त अधिकरण में सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति जो न्यायिक प्रक्रिया से अनभिज्ञ हैं उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता को प्रभावित करेगा। यही अन्य न्यायिक अधिकरणों के सम्बन्ध में आम वादकारियों का अनुभव है।

यह आवश्यक रूप से स्मरण दिलाना आवश्यक है कि निष्पक्ष न्याय व स्वतन्त्र विधायिका के लिए सिद्धान्ततः न्यायपालिका एवं कार्यपालिका में दूरी बनाए रखना आवश्यक है।

श्रद्धेयवर, हम प्रयागराज के विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि के रूप में केवल न्यायपालिका की अक्षुण्णता को बनाए रखने के साथ-साथ प्रयागराज के विकास में होने वाली क्षति के परिप्रेक्ष्य में आपसे आग्रह करते हैं जो कि सर्वोच्च न्यायालय एवं प्रान्तीय उच्च न्यायालयों ने भी व्यवस्था दी है कि यदि ऐसे न्यायिक अधिकरण बनाना आवश्यक है तो प्रानतीय उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ के साथ ही उसकी स्थापना की जाय जिससे न्यायपालिका का गौरव एवं उसकी स्वतंत्रता बनी रहे।"

उपस्थित सदस्यों ने एकमत होकर निर्णय लिया कि वर्तमान परिस्थितियों में प्रयागराज के प्रति सरकार की उदासीनता और प्रयागराज की जनता की समस्याओं के प्रति सरकार की उदासीनता को देखते हुए एक ऐसे संगठन की आवश्यकता है जो कि प्रयागराज व प्रयागराज के नागरिकों की सामूहिक समस्याओं के लिए संघर्ष करने में सक्षम हो और प्रयागराज की क्षीण होती शक्ति, गरिमा, गौरव व महिमा को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक रूप से पुनर्स्थापित कर सके।

सभा में सर्वसम्मति से यह सुनिश्चित किया गया कि उपरोक्त के क्रम में उपस्थित नागरिक संस्थाओं व संगठनों के पदाधिकारी औपचारिक रूप से एक संगठन की स्थापना करेंगे जिसके लिए हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं महासचिव को अधिकृत किया गया है।

Website : <http://www.hcbaallahabad2018.in> | Email : highcourtbaralld@gmail.com

Phone : 0532-242 1942 | Fax : 0532-242 0404